RAJYA SABHA

Tuesday, the 1st March, 1994/10th Phalguna, 1915 (Saka)

The House met at eleven the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

*81. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विचाराधीन/निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा प्रत्येक विद्युत परियोजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में कितनी प्रगति हुई है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The names of generation projects, their estimated capacity, the likely date of commissioning, funds allocated and the implementation status of projects under construction in Uttar Pradesh are indicated in Annexure-I [See Appendix 170, Annexure No. 17]. Besides these, there are certain projects which have been accorded techno-economic clearance by the Central Electricity Authority but require other sanctions. These are indicated in Annexure-II. [*See* Appendix 170, Annexure No. 18].

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर सभापति जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन विद्युत के अभाव के कारण यहां कृषि बुरी तरह से प्रभावित है, उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, सारी परेशानियां हैं। मंत्री जी का जो उत्तर है, इसको देखने से यह लगता है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के प्रति उदासीन है क्योंकि हमने जो प्रश्न पूछा था, इसका इन्होंने जो उत्तर दिया है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि केन्द्र सरकार की सारी की सारी योजनाएं अधूरी है, कोई भी योजना पूरी होने की स्थिति में नहीं है और कुछ योजनाओं को इन्होंने कहा जैसे "टांडा" की योजना है, "धौलीगंगा" है, इनको कहा है कि 8वीं योजना में भी पूरी होने की कोई आशा नहीं है और कुछ योजनाओं के बारे में इन्होंने कहा है कि 8वीं योजना या इसके बाद पूरी होने की आशा है। हमने एक निश्चित समय पूछा था कि किस समय तक ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन किसी भी योजना के बारे में कोई स्पष्ट और सही उत्तर नहीं दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के बारे में उदासीन क्यों है? जिन योजनाओं का आपने उल्लेख किया है और जिनके बारे में मैंने जानना चाहा है, उनके बारे में मैं आपका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि ये योजनाएं किन-किन कारणों से अधूरी है, किन-किन कारणों से पूरी नहीं हो पा रही है और ये योजनाएं निश्चित रूप से कब तक पूरी हो जाएंगी, यह मैं जानना चाहता हूं?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Mr. Chairman, Sir, there are some Central Government projects and State Government projects which are in progress in the State of Uttar Pradesh. Out of these, Anpara 'B' with an installed capacity of 2x500 MW, Tanda with 100 MW, Sobla, a small project with 2x3 and Rajghat with 15x3 MW will be completed in the Eighth Plan and the remaining projects are likely to switched over to the Ninth Plan for want of resources. The Uttar Pradesh Government is not able to provide the necessary resources required for taking up these projects due to their financial resource crunch. The Government of India is ready to come to the aid of the Uttar Pradesh Government, wherever necessary. If it is a joint project like Tehri, we are prepared to put in our share of money but the Uttar Pradesh Government is not prepared to put in their share of money. So it is not correct to say that the Government of India is

neglecting the projects in the State of Uttar Pradesh.

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): Sir, I may add to what my colleague has already said. हम लोग उत्तर प्रदेश की जितनी हमारी परियोजनाएं है ऊर्जा की, उनके प्रति बिल्कुल उदासीन नहीं हैं, उनको चुस्ती से हम पूरा करना चाहते हैं "टिहरी" सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जो सी०सी०ए० ने एप्रूव कर ली है। 160 करोड़ का प्रावधान 1994-95 में कल मनमोहन सिंह जी ने करके दिया है, यू०पी० गवर्नमेंट से 140 करोड़ आता है, अगर यू०पी० गवर्नमेंट से आप थोड़ा अपना प्रभाव चलाएं और उनका जो हिस्सा है, वहां भी आ जाए साथ-साथ तो कम से कम हमने जो अभी नया लक्ष्य रखा है समय का, वह पूरा कर पाएंगे, यह मेरा माननीय सदस्य से बहुत नम्र निवेदन है।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत विजिलेंट है इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं बल्कि मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि केन्द्र सरकार उदासीन है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक अनपारा-बी प्रोजेक्ट है और इसका परिव्यय 716 करोड़ रुपए है। इसमें 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का हिस्सा है और 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार का हिस्सा है। प्रदेश सरकार ने अपने धन की स्वीकृति दे दी है और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से 19.10.93 को आपकी वार्ता हुई थी और 19.10.93 की उस वार्ता में राज्यपाल महोदय ने आपसे आग्रह किया था अगर आप 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दें तो अनपारा-बी प्रोजेक्ट में काम आगे बढ़ सकेगा लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि आपने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। मुझे पता नहीं है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी लेकिन राज्यपाल महोदय ने जो आपसे आग्रह किया था, मांग की थी 32 करोड़ रुपए के लिए, वह रुपया भी आप नहीं दे रहे हैं। यह मेरी निश्चित जानकारी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस धन को आप प्रदेश सरकार को कब तक देंगे?

इसके साथ ही मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि श्रीनगर कम्पोजिट प्रोजेक्ट और विष्णुप्रयाग योजना, ये दोनों योजनाएं भी केन्द्र सरकार की नैग्लिजेंस की वजह से या केन्द्र सरकार के दिलचस्पी न लेने के कारण आज तक लंबित पड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं की स्वीकृति आप कब तक देंगे और इसके लिए कब तक धन आवंटित कर देंगे ताकि इन योजनाओं को पूरा किया जा सके।

SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: Mr. Chairman, Sir, the Anpara Project is a State project. So, there is no question of the Government of India giving its share of money for Anpara 'B' project. In spite of this, the Government of India has come to rescue of the Government of *Uttar Pradesh on two previous occasions.* In 1991-92, an amount of Rs. 27 crores had been given to the UPSEB. Again in 1992-93, the Government of India prevailed upon the Customs Department to waive the Customs duties to the extent of Rs. 156 crores to enable the Board to import the equipment. In 1994, the Uttar Pradesh Government has requested for Rs. 138.50 crores to which the hon. Member referred. But a final view is yet to be taken by the Government of India. *The Government of India is likely to give* the Customs duty exemption as in the previous years but to the extent of Rs. 75 crores. Besides the above, the Government of India released during this year Rs. 35 crores to the Government of Uttar Pradesh for related OECF works. But my information is that the above amount has not been passed on by the Uttar Pradesh Government to the UPSEB.

SHRI N.K.P. SALVE: And they are blaming us.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: श्रीमान, जितनी योजनाएं हैं, उनमें से बहुत पर लिखा हुआ है कि हर जगह यह लिखा हुआ है। तो यह फंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, यह बताने की कृपा करें और खास तौर से मैं ध्यान दिलाऊंगा टिहरी डैम पर। इस बारे में लिखा हुआ है कि Project progress is affected by fund constraints. उस प्रोग्रेस का मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि इसके लिए वित्त मंत्री जी ने कल बजट में पैसा दिया है वह बात तो ठीक है लेकिन सवाल यह है कि वहां काम चालू है या नहीं।

मैं गत वर्ष वहां गया था, मैंने खुद देखा है, वहां ब्लास्टिंग भी बंद कर रखी है मैं जानना चाहूंगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है और इस डैम के लिए जो

विदेशी पैसा आना था रशियां से, उसकी पूर्ति के लिए आपने क्या किया है? खास तौर से मैं ब्लास्टिंग के बारे में पूछूंगा।

यहां से कोई आर्डर ब्लास्टिंग बंद करने के लिए गया नहीं। दो तीन साल से वहां काम बंद है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि टेहरी डैम किस स्टेज पर है। दूसरे, इनकी जो कांस्ट्रेंट्स 5 और 6 पर दी गई है, वह क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री संघ प्रिय गौतम: काम तो चालू नहीं है, पर मंत्रालय बड़ा चालू है।...

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member was referring in general to the delay of the projects due to financial constraints, and in particular about the Tehri project. The problem with the UPSEB, Sir, is that it has suffered a cumulative loss amounting to Rs. 455 crores at the end of 1991-92. As a result, they are not able to create any surplus or any capital for taking up works for the projects completition. Sir, so far as...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The issue is what part the Government of India is going to play in that. आप को कितना पैसा देना था और आप कितना पैसा दे रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: He is going to say that.

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: I am going to reply to that, Sir so far as the State Projects are concerned, the State must find its own resources. If it is a joint sector project, the money will be given by the Central Government to the extent it is committed to. Tehri is a joint sector project. Up to March, 1993, an amount of Rs. 766 crores has been spent. Out of this, the UP Government Claims to have given Rs. 209 crores. But so far, in the Eighth Five-Year Plan, the UP Government has not given anything for the Tehri project. In the coming year, the UP Government is expected to give Rs. 140 crores. We do not know how much the UP Government will be able to give. And the Government of India has provided Rs. 160 crores in the coming year for this project. The Government of India will release this. And this year, we have already released Rs. 97 crores. And another Rs. 23 crores are also going to be released for Tehri. But the UP Government has not given anything so far in 1993-94. I am submitting, Sir, that the UP Government has not given anything in 1993-94. We have already released Rs. 97 crores and another Rs. 23 crores also are going to be released. The revised estimate for Tehri is Rs. 120 crores for the year 1993-94. And we have released Rs. 93 crores already.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: 1993 का आप कह रहे हैं, वहां पैसा पहुंचा है?

Has the money really reached the Corporation? The fund that you are supposed to have released, has it reached them?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Yes, Sir.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Because, as I know, what ever you gave last year was really spent on salaries, etc., and not on works.

SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: No, no...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The work there is stopped. Mainly blasting has been allowed.....

SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: No, Sir. I am coming to that. This year, we have released Rs. 97 crores, and works to that extent have been executed, including the money to be spent on the administration and rehabilitation. Another Rs. 23 crores are going to be released before the end of March this year. So, there is no negligence or lack of interest on the part of the Government of India. Unfortunately, the State Government of Uttar Pradesh is not able to provide its counterpart funds. I am told, the Chief Minister has agreed to provide Rs. 140 crores, to be spent in 1994-95. As a result nothing would have come to us for 1993-94. As mentioned by

my senior colleague, only recently the CCEA has cleared the project at a cost of Rs. 2963 crores for the first stage, and Rs. 317 crores for the associated transmission for the current Five-Year Plan. Out of this, as I have already said, we have spent about Rs. 766 crores up to last year, and another Rs. 120 crores this year. It will be about Rs. 886 crores. The balance will be provided in the remaining years of the Eighth Five-Year Plan, and the project can be completed provided the UP Government comes forward with its counterpart funds.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, the imputations in the question of Mr. Mathur are not only uncharitable, but they are also wholly unjustified. We have released a sum of Rs. 97 crores in 1993-94, and for 1994-95, and Rs. 140 crores have to come from the State Government of U.P. The State Government is showing all co-operation. About blasting which he referred to, there was some agitation going on, and you wanted us to carry on the blasting but there was a law and order problem which is not our problem. It is the problem of the State Government. So far, we did not receive any co-operation. Now the Mulayam Singh Government is extending full co-operation. The agitation was being carried on by some supposed environmentalists but the State Government said: 'You go ahead with your work. These people carrying on agitations are anti-growth in U.P. and we will take care of them.' They promised to release Rs. 140 crores. Here, I am not supporting anybody; I am not rejecting I am not criticising anybody. I am only interested in getting through the project. And for the purpose of implementation of the project, I want to give an assurance on the floor of the House that we will not leave any stone unturned to implement the project. It is an important project for us. About 40 lakh people in Delhi will get drinking water out of it, apart from water for irrigation and apart from power. It is a multipurpose, prestigious and an important project for U.P. and we will do our best to implement it.

श्री राम नरेश यादव: मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर में एक संलग्न-एक है और दूसरा संलग्न-दो है। जो प्रथम है उसमें जो चालू परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा है और दूसरे में जो योजनाएं सीईए द्वारा सैंक्शंड हैं उनके बारे में है। मैं जानना चाहता हूं संलग्न दो में जो आपने लिखा है हाइड्रो और थरमल दोनों पर 'Projects in U.P. accorded techno-economic clearance by the C.E.A. but awaiting other sanctions. मैं जानना चाहता हूं कि वह अवेटिंग अदर्स सैंक्शन क्या हैं जिनके बारे में अभी तक इन प्रोजेक्ट्स को क्लीयर नहीं किया जा सका उसको स्पष्ट करें? दूसरा भाग मेरा यह है कि आपने संलग्न एक में दिया है कि सारी योजनाएं चल रही हैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 93-94, 94-95 के लिए इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि मांगी थी टोटल और केन्द्रीय सरकार ने कितनी उसमें से देने का वचन दिया है, सैंक्शन किया है? यह बी पार्ट है। इन दोनों का उत्तर मैं जानना चाहता हूं।

SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: I will write to the hon. Member. He may give me the details. I will write to him if you permit me. I have got here the details and I can read out if you permit.

MR. CHAIRMAN: You can write to him.

श्री राम नरेश यादव: मेरा प्रश्न यह है कि इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कुछ कारणों की वजह से नहीं कर पाये हैं। मंत्री जी को कम से कम इसको बताना चाहिए। इसमें क्लीयर लिखा है अवेटिंग अदर सैंक्शंस तो वे अदर सैंक्शंस क्या हैं जिसकी प्रतिक्षा सरकार कर रही है? यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिजली की डिमांड बढ़ रही है, खेती के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में उसको ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पूरे देश की एक बटा छः भाग जनसंख्या है, उसमें वैसे ही बड़ी-बड़ी योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सामने कोई बात विचाराधीन है? करीब 8-10 साल लग जाते हैं इसको पूरा करने के लिए। अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: There are four projects which are

included in Annexure 2 "Projects in U.P. accorded techno-economic clearance by the C.E.A. but awaiting other sanctions." These sanctions relate to investments approval to be given by the Government of India.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: सभापति महोदय, बिजली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपने उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं अभी आर्थिक दृष्टि से स्वीकार की हैं उनको अनेक्शचर-ए में दिया है। और उसमें यह भी कहा गया है—एक है 10 नंबर पर कि जो योजना श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल की है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसके लिये 93 और 94 में कोई भी धन आवंटित इस संबंध में नहीं किया गया और आगे लिखा है कि परियोजना के कार्य की प्रगति निधियों के अभाव के कारण आठवीं योजना में भी पूरी नहीं की जा सकेगी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 93-94 में इसकी आर्थिक स्वीकृति मौजूद थी तो इसके लिये धन क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि जब आठवीं योजना में भी इसके पूरा होने की संभावना नहीं है तो जिस क्षमता से यह बनाया जा रहा है तो यह उस क्षमता को देखते हुए जब नौवीं और दसवीं योजना में यह पूरी होगी तो क्या उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये इस क्षमता से वह असक्षम नहीं होगी?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: In regard to the projects mentioned in Annexure II, it is very clearly mentioned in column 4 that the likely target date for commissioning is 'Ninth Plan and beyond'. Therefore, there is no question of completing these projects in the Eighth Five-Year Plan. That is why no allocation has been made during 1993-94. These projects are yet to be taken up and, therefore, the question of allocation of funds in the Eighth Five-Year Plan, or expenditure in the Eighth Five-Year Plan, does not arise.

Improvement of Stock Market

*82. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are adequately equipped to assess artificial improvement of market sentiment in our stock market due to the available liquidity with Foreign Institutional Investors (FIIs);

(b) if so, the details of the system by which Government notes buoyancy in the market and the reasons therefore; and

(c) the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Government as well as the Securities and exchange Board of India (SEBI) have been continually monitoring and assessing the various stock price indices and trends in the stock market. The improvement of market sentiment in the recent past is a consequence of several factors which operate with differing intensity at different moments of time. These factors include the substantial purchases of shares by Foreign Institutional Investors (FIIs), investments in the stock markets by new mutual funds and new schemes of existing mutual funds, a shortage of scrips because of the resort to GDR issues by Indian companies and the delay in effecting public sector disinvestment expectations of investors relating to improvements in the overall economic environment, general improvement in the performance of the corporate sector as reflected in unaudited half-yearly financial results, as well as an element of speculation of varying intensity which characterises most stock markets in the world.

(c) The custodians for the FIIs are required to send details of the transactions entered into by the FIIs on a daily basis to SEBI. The total inflow as of 24.2.94 amount to Rs. 4139 crores. (US $ 1.335 Billion) Thus the amount of purchases and sales by FIIs can be computed and the flow of funds